संज्ञान लेने लायक एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1980 के दशक के बाद से पूरे संसार में सार्वजनिक/शासकीय प्रशासन के बारे में गम्भीर पुनर्विचार होता रहा है और 'नया सार्वजनिक/शासकीय प्रबन्धन' एक उदाहरणस्वरूप उभरकर आया है जिसके तहत पक्के सरकारी कर्मचारी होने की बजाए लोगों को अनुबन्ध पर लगाने तथा कार्य को बाहरी एजंसियों को देने की प्रवृत्ति रही है। इस सोच का प्रभाव हमें कई राज्यों में पैरा-शिक्षकों को बड़े पैमाने पर भाड़े पर लगाने की शक्ल में दिखाई देता है। देश की आजादी के समय सरकार का आकार बढ़ाने तथा एक स्थाई नौकरशाही की बात को व्यापक तौर पर स्वीकृति प्राप्त थी। 1990 के दशक से इन बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे काम की स्थितियों में और परिणामस्वरूप शिक्षकों के काम करने की शैली में भी बड़ा बदलाव आया है। ध्यान देने की बात यह है - जबकि नए सार्वजनिक प्रबन्धन ने विकसित देशों में परिपक्व लोकतंत्रों के परिप्रेक्ष्य में जड़ पकड़ी थी, हमारे नए लोकतंत्र में इसकी गतिशीलता अलग तरह की रही है। हमें जाँचना होगा कि क्या इससे शिक्षकों के काम के हालात में संरक्षण और प्रश्रय तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है?

सार की बात यह कि शिक्षक और उनका काम उस सरकार के परिप्रेक्ष्य में स्थित हैं जिसे संविधान, राजनीति और नौकरशाही ने ढाला है। सरकार की प्रकृति बदलने के साथ ही शिक्षकों पर भी समानान्तर प्रभाव दिखाई देता है। शिक्षक को समझने के लिए हमें न केवल शैक्षिक नीतियों और प्रथाओं को बल्कि सरकार को भी समझना होगा। सरकार के बारे में कुछ उल्लेखनीय बिन्दुओं पर ऊपर रोशनी डाली गई है लेकिन शिक्षक को पूरी तरह समझने और मदद के लिए सरकार की एक वास्तव में विस्तृत समझ बनाना आवश्यक है।

रश्मि शुक्ला शर्मा 1984 के बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वे मध्य प्रदेश काडर से हैं। उन्होंने केन्द्रीय और राज्य सरकार में अलग-अलग पदों पर, तथा स्कूली शिक्षा और पंचायती राज में कई साल काम किया है। उन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं – 'भारत में स्थानीय शासन : नीति और व्यवहार' तथा 'भारत में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था' (विमला रामचन्द्रन के साथ मिलकर सम्पादित)। शिक्षा तथा स्थानीय शासन पर कई लेख भी लिखे हैं। उनसे rashmishuklasharma@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** रमणीक मोहन